पत्र संख्या–15/बि0स0से0–02–01/2017 सा0प्र0................../
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी आयोग के सचिव
पुलिस महानिदेशक का कार्यालय
मुख्यमंत्री सचिवालय
महाधिवक्ता का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक......................

विषयः–विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कार्यरत निदेशालयों को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 26 दिनांक 02.01.2018 द्वारा विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कार्यरत निदेशालय/आयोग/ट्रिब्यूनल, जिनका नाम बिहार सचिवालय सेवा नियमवाली, 2010 के परिशिष्ट–1 में शामिल नही है, को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त के क्रम में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत कार्यरत निदेशालय/आयोग/ट्रिब्यूनल को सचिवालय का संलग्न कर्यालय घोषित किये जाने के विचारार्थ निम्न सूचना के साथ प्रस्ताव की आवश्यकता हैः–

1) प्रस्तावित निदेशालय/आयोग/ट्रिब्यूनल को सरकार का एक स्थायी विभाग घोषित किये जाने संबंधी संकल्प।

2) निदेशालय/आयोग/ट्रिब्यूनल प्रमुख का स्टेटस विभागाध्यक्ष घोषित किया गया हो तथा उन विभागाध्यक्ष को सारी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियॉ प्रदत्त की गई हो, संबंधी संकल्प।

3) निदेशालय/आयोग/ट्रिब्यूनल में पदों की सृजन संबंधी सूचना।

4) प्रशाखा पदाधिकारी, सहायक आदि के पद के सृजन संबंधी सूचना।

5) उक्त पदों को स्थायी पद घोषित होने एवं उक्त पदों पर होने वाली व्यय की निकासी सचिवालय सामान्य सेवाएँ–सचिवालय अन्य कार्यालय के अन्तर्गत करने का निर्णय लिया गया हो।

6) संलग्न कार्यालय बनाने का उद्देश्य।

अतः अनुरोध है कि उक्त सूचना के साथ प्रस्ताव इस विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि संबंधित निदेशालय/आयोग/ट्रिब्यूनल को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने पर विचार किया जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/–

(सिद्धेश्वर चौधरी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- 14638 दि० - 6.11.18

प्रतिलिपिः– आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।